रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062026-273860
CG-DL-E-26062026-273860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948
No. 168]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASADHA 1, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

[व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)]

जांच शुरूआत की अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

मामला सं. – ए डी (ओआई) (15/2026)

सेतु मामला आईडी सं.-एडी/ओआई/016/2026

विषय: चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सीआरजीओ) और एमॉर्फस मेटल (एएम)" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा.सं. 6/17/2026-डीजीटीआर.— समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (क्षति के निर्धारण के लिए पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "एडी नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, जे एस डब्ल्यू जेएफई इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने "कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सी आर जी ओ) और एमोर्फस मेटल (ए एम)" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की मांग की है। तथापि, डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों और आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र की जांच करने पर, यूरोपीय संघ के मामले में नकारात्मक पाटन मार्जिन देखा गया। अत:, प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू नहीं की है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य और रूस को संबद्ध देश माना है (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा जाएगा)।

3. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों से वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद ("पी यू सी") (i) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील ("सी आर जी ओ") और (ii) एमॉर्फस मेटल ("एएम") है।

5. सी आर जी ओ एक फ्लैट-रोल्ड मिश्र धातु इस्पात उत्पाद है जिसमें भार के अनुसार कम से कम 0.6 प्रतिशत लेकिन सिलिकॉन (एसआई) के 6 प्रतिशत से अनधिक होता है, चाहे वह कॉइल में हो या शीट के रूप में या लैमिनेशन के रूप में हो। ए एम, सीधे प्रतिस्थापनीय उत्पाद, लौह के साथ पिघले हुए मिश्र धातु के अल्ट्रा-रैपिड क्वेंचिंग द्वारा उत्पादित एक गैर-क्रिस्टलीय संरचना वाला मिश्र धातु है और तदनुसार उत्पाद क्षेत्र में शामिल है।

6. सी आर जी ओ और एएम दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं जिनका प्रयोग विद्युत ट्रांसफार्मर में कोर सामग्री के रूप में किया जाता है। आवेदक ने दावा किया है कि एमॉर्फस मेटल (ए एम) और कोल्ड-रोल्ड ग्रेन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील (सी आर जी ओ) वास्तविक रूप से समान नहीं हैं, लेकिन तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय और परस्पर परिवर्तनीय हैं।

7. सी आर जी ओ और ए एम सामग्री का मुख्य अंतिम उपयोग बिजली/वितरण ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए है। दोनों सामग्रियों का उपयोग समान उपभोक्ता उद्योगों द्वारा किया जाता है, अर्थात ट्रांसफार्मर निर्माता, उपयोगिताओं, औद्योगिक प्रयोक्ताओं और नवीकरणीय बिजली परियोजनाओं को आपूर्ति करते हैं। अंतिम प्रयोग के परिप्रेक्ष्य से, दोनों सामग्री कार्यात्मक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं।

8. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित को बाहर रखा गया है:

(i) बिजली/वितरण ट्रांसफार्मर के उत्पादन को छोड़कर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली अमोर्फस धातु।

(ii) सब्सट्रेट के रूप में सी आर जी ओ के निर्माण में प्रयोग के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड (एम जी ओ) कोटिंग वाले कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल।

<u>माप की इकाई</u>

9. विचारधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एम टी) या किलोग्राम (के जी) है।

<u>प्रशुल्क वर्गीकरण</u>

10. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 7225 1100, 7226 1100 और 7226 9930 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, कुछ अन्य एच एस कोड अर्थात 7225 1920, 7225 1990, 7226 1920, 7226 9910, 7226 1990, 7226 99 10, 7226 99 20 और 7226 9990 में भी विचाराधीन उत्पाद का आयात पाया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

11. आवेदक ने किसी पी सी एन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है। वर्तमान जांच के पक्षकार जांच की शुरूआत की सूचना की प्राप्ति के परिचालन के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या (पी सी एन) पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, दें।

ख. समान वस्तु

12. आवेदक सीआरजीओ का उत्पादक है लेकिन अमोर्फस धातु का नहीं है। आवेदक ने दावा किया कि यद्यपि एमॉर्फस मेटल और सी आर जी ओ की अलग-अलग वास्तविक संरचनाएं हैं, वे समान कार्यों को पूरा करते हैं, समान उपभोक्ताओं द्वारा समान अंतिम उपयोग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, बाजार और विनियामक निकायों द्वारा परस्पर परिवर्तनीय के रूप में माने जाते हैं और कीमत और निष्पादन के संबंध में सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं।

13. आवेदक ने दावा किया कि आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध सामान और वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता संबद्ध सामानों और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तुओं का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु माना गया है।

14. आवेदक ने उल्लेख किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देशों से आयातित वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और संबद्ध सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। संबद्ध सामान और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता आवेदक द्वारा निर्मित संबद्ध सामानों और समान वस्तुओं का परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद की समान वस्तु मानी गई है।

ग. संबद्ध देश

15. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण., जापान, कोरिया गणराज्य और रूस हैं।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

16. आवेदक ने शुरू में जांच की अवधि 9 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 (9 महीने) और क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2022 से -31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से -31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से -31 मार्च 2025 और जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित की थी। इसके बाद, आवेदक ने जांच की अवधि को 12 महीने अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक संशोधित करने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का अधिक सटीक और व्यापक मूल्यांकन किया जा सकेगा। अत:, आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधित अवधि को जांच के उद्देश्य के लिए उपयुक्त माना गया है और तदनुसार प्राधिकारी ने वर्तमान जांच (जिसे इसके बाद "पीओआई" कहा गया है) के लिए जांच की अवधि (पीओआई) को 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 (12 महीने) और क्षति की जांच की अवधि को 1 अप्रैल 2022 से -31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से -31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से -31 मार्च 2025 के रूप में मानने का निर्णय लिया है

ड. घरेलू उद्योग और आधार

17. वर्तमान जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र जेएसडब्ल्यू जेएफई इलेक्ट्रिकल स्टील नासिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

18. आवेदक ने अनुरोध किया है कि एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड आवेदक के अलावा विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र अन्य घरेलू उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड रूस से संबद्ध सामानों के निर्यातक से संबद्ध है और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबद्ध है।

19. यह भी अनुरोध किया जाता है कि एन एल एम के ग्रुप रूस ने क्षति की जांच की अवधि के दौरान भारत को पर्याप्त मात्रा में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। एन एल एम के इंडिया सर्विस सेंटर प्रा. लि. एन एल एम के ग्रुप रूस से संबद्ध सामानों का आयातक है। एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध है और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबद्ध है। इसलिए, आवेदक ने अनुरोध किया है कि एन एल एम के इंडिया कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।

20. एक अन्य घरेलू उत्पादक एन एल एम के के विचार मांगे गए हैं, जिसमें उनसे संबद्ध देश से उनके या संबद्ध कंपनियों द्वारा किए गए आयात के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और क्या वे संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के उत्पादकों और निर्यातकों से संबद्ध हैं और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबंद्ध हैं। एन एल एम के इंडिया ने अनुरोध किया है कि रूस में उसकी संबद्ध कंपनियों, नोवोलीपेत्स्क स्टील और विज़ स्टील लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान भारत को काफी निर्यात किया है। एन एल एम के इंडिया ने यह भी अनुरोध किया है कि उसकी भारत में एक संबद्ध इकाई एन एल एम के इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान रूस, नोवोलीपेत्स्क स्टील और विज़ स्टील लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में अपनी संबद्ध कंपनी से संबद्ध सामानों का आयात किया था। प्राधिकारी ने नोट किया है कि नोवोलीपेत्स्क स्टील और विज़ स्टील लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी द्वारा निर्यात/एन एल एम के इंडिया सर्विस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयात जांच की अवधि के दौरान रूस से कुल आयात, कुल भारतीय उत्पादन और एन एल एम के इंडिया द्वारा उत्पादन की तुलना में काफी मात्रा में हैं।

21. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन एल एम के इंडिया रूस में संबद्ध सामानों के उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध है और भारत में संबद्ध सामानों के आयातक से भी संबद्ध है। तदनुसार, एन एल एम के इंडिया पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अभिप्राय से एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं है।

22. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना और पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* मानते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के अभिप्राय से एक पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षा को पूरा करता है।

च. तथाकथित पाटन का आधार

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

23. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध- I के नियम-7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(3) के अनुसार संबद्ध सामानों के उत्पादन वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. के लिए, सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध- I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

24. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, आवेदक को किसी तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या लागत की सूचना के संबंध में विश्वसनीय सूचना नहीं मिल सकी। अत:, उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए समायोजित आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है। जांच की शुरूआत करने के उद्देश्य से भी ऐसा ही माना गया है। चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के सामान्य मूल्य के संबंध में आवेदक द्वारा दावा किए गए पर्याप्त साक्ष्य हैं।

ख. जापान, कोरिया गणराज्य और रूस के लिए सामान्य मूल्य

25. आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह जापान, कोरिया गणराज्य और रूस में संबद्ध सामानों की तुलनीय कीमतों पर सूचना प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। यह सूचना किसी भी सार्वजनिक स्रोत से भी उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, चूंकि संबद्ध सामानों का आयात विभिन्न कोडों के तहत किया जा रहा है, इसलिए संबद्ध देशों से तीसरे देशों को निर्यात किए जाने पर संबद्ध सामानों के प्रतिनिधि मूल्य के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसे देखते हुए, आवेदक ने सामान्य मूल्य के आधार के रूप में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित अतिरिक्त लाभ के साथ, भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जापान, कोरिया गणराज्य और रूस के लिए सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया है। जांच की शुरूआत के उद्देश्य से इसे ही माना गया है।

ग. निर्यात कीमत

26. आवेदक ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। तथापि, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की निर्यात कीमत के निर्धारण के उद्देश्य से, कारखानागत निर्यात कीमत का पता लगाने के लिए डीजी सिस्टम आंकड़ों को अपनाया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, क्रेडिट लागत, बंदरगाह व्यय और सार-संभाल शुल्क के निमित्त समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

27. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

28. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबद्ध देशों से संबद्ध आयात की मात्रा निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही रूप में बढ़ी है। आयात के कारण कीमत ह्रास और न्यूनीकरण का प्रमाण है। संबद्ध आयात का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

29. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच शुरू करने का औचित्य बनाने के लिए, तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए, और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए तथाकथित पाटन और मौजूदा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तथा घरेलू उद्योग को क्षति का संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन का प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पाते हैं।

ज. शुल्क पूर्वव्यापी रूप से लगाना

30. आवेदक ने निम्नलिखित का दावा करते हुए पाटनरोधी शुल्क पहले से लगाने का अनुरोध किया है:

क. संबद्ध देशों से उत्पाद के पाटन का स्पष्ट इतिहास है।

ख. भारत में आयातक इस तथ्य से अवगत हैं कि निर्यातक भारत में संबद्ध सामानों का पाटन करते हैं। आयातक भी इस तथ्य से अवगत हैं कि इस तरह की परिपाटी से भारतीय उत्पादकों को क्षति होगी।

ग. निर्यातकों ने बड़े पैमाने पर पाटन का सहारा लिया है और जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन काफी रहा है।

घ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में भारी गिरावट आई है।

31. आवेदक ने अनंतिम शुल्क लगाने की तारीख से पहले नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए पूर्वव्यापी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया है।

32. प्राधिकारी इस संबंध में अधिसूचना में दी गई समय सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध/टिप्पणियां मांग सकते हैं।

झ. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

33. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, संतुष्ट होने पर, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति तथा उस क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने और पाटनरोधी शुल्क की उचित राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरु करते हैं।

ञ. प्रक्रिया

34. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना प्रस्तुत करना

35. सभी हितबद्ध पक्षकारों को स्वयं को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in/) पर पंजीकृत करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारो से सभी पत्र और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु मामला सं.-एडी/ओई/016/2026 पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और आंकड़ा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।

36. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, और भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं को संबद्ध सामानों से संबंधित होने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच की शुरुआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

37. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार नियमावली और इस जांच की शुरुआत में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों, जांच की शुरुआत में निर्धारित स्वरूप और तरीके से वर्तमान जांच के संगत अनुरोध भी कर सकता है।

38. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।

39. इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए हितबद्ध पक्षकारों को व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहने और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धि, संशोधन अधिसूचनाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के संबंध में अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें।

ठ. समय सीमा

40. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामला आईडी-एडी/ओआई/016/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए।

41. प्रत्येक अनुरोध के दोनों रूपांतर, गोपनीय रूपांतर (सीवी) और अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) को आवेदन-पत्र का अगोपनीय रूपांतर प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने की तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते है।

42. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के बारे में सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें।

43. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति के संबंध में टिप्पणियां दायर करने के लिए 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना के पैरा 41 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

44. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद की सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन को संशोधित करते है, जिसे पहले प्रस्तावित नहीं किया गया था या जो जांच शुरुआत

अधिसूचना से अलग है, तो समय का 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन की उस अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय बढ़ाना उन उदाहरणों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, समय के और विस्तार (यदि प्रदान किया जाता है) के अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

45. समय विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा ऊपर निर्धारित मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

46. किसी भी पक्षकार को प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध या गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले किसी पक्षकार के लिए यह अपेक्षित है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय रूपांतर साथ साथ प्रस्तुत करें। उपर्युक्त का अनुपालन न होने की स्थिति में उत्तर/अनुरोधों को रद्द किया जा सकता है।

47. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्टों/उनके साथ संलग्न अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय रूपांतर, अलग-अलग दायर करना अपेक्षित है।

48. ऐसे अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को ऐसे चिह्नों के बिना किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों को देखने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

49. गोपनीय रूपांतर में वह पूरी सूचना निहित होगी जो प्रकृति से गोपनीय है, और/या अन्य सूचना, जो उस सूचना देने वाले ने गोपनीय होने का दावा किया हो। प्रकृति में गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए, या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना देने वाले के लिए यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ अच्छे कारण वाला विवरण दें कि वह सूचना प्रकट क्यों नहीं की जा सकती।

50. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होनी चाहिए, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और यह सूचना गोपनीयता का दावा की गई सूचना के आधार पर उपयुक्त रूप से और पर्याप्त रूप से सारभूत की जानी चाहिए। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह दर्शा सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं पूर्ण स्पष्टीकरण से युक्त कारणों का विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए आवश्यक रूप से यह दर्शाना चाहिए कि वह सार संभव क्यों नहीं है।

51. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

52. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना देने वाला सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखा कर सकते हैं।

53. गोपनीयता के दावे के संबंध में, नियमावली के नियम 7 के अनुसार, सार्थक अगोपनीय रूपांतर या पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना, और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ढ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

54. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय रूपांतरों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ कराया जाएगा।

ण. असहयोग

55. यह कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उपयुक्त अवधि के भीतर सूचना देने से इंकार करता है और अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं देता है, या जांच में पर्याप्त रूप से बाधा डालता है तो प्राधिकारी उस हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

[Directorate General of Trade Remedies (DGTR)]

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

Case No. AD(OI) (15/2026)

SETU Case Id No - AD/OI/016/2026

Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO) and Amorphous Metal (AM)" originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, and Russia.

F. No. 6/17/2026-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "AD Rules" or the "Anti-dumping Rules"), JSW JFE Electrical Steel Nashik Private Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority"), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel (CRGO) and Amorphous Metal (AM)" (hereinafter referred to as "subject goods" or "product under consideration" or "PUC").

2. The Applicant has sought anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Russia and European Union. However, upon examination of the data received from the DG Systems and the application filed by the applicant, negative injury margin was observed in the case European Union. Hence, the Authority has not initiated anti-dumping investigations against European Union. The Authority has considered China PR, Japan, Korea RP and Russia as the subject countries in the present investigation (hereinafter referred to as "subject countries").

3. The Applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from the subject countries is causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

4. The product under consideration ("PUC") in the present investigation is (i) Cold Rolled Grain Oriented Electrical Steel ("CRGO") and (ii) Amorphous Metal ("AM").

5. CRGO is a flat-rolled alloy steel product containing by weight at least 0.6 percent but not more than 6 percent of Silicon (Si), whether in coils or in sheet form or in lamination form. AM, a directly substitutable product, is an alloy with a non-crystalline structure produced by ultra-rapid quenching of molten alloy with iron and is accordingly included in the product scope.

6. Both CRGO and AM are magnetic materials used as core material in electrical transformers. Applicant has claimed that Amorphous Metal (AM) and Cold-Rolled Grain-Oriented Electrical Steel (CRGO) are not physically identical but are technically and commercially substitutable and interchangeable.

7. The principal end-use of CRGO and AM materials is for manufacture of power / distribution transformer cores. Both materials are used by the same consumer industries i.e. transformer manufacturers supplying to utilities, industrial users, and renewable power projects. From the perspective of end-use, the two materials are functionally interchangeable.

8. The following are excluded from the scope of PUC:

    i. Amorphous Metal used for purposes other than production of power/distribution transformers.

    ii. Magnesium Oxide (MgO) coated cold rolled steel coils for use in manufacture of CRGO as substrate.

Unit of measurement

9. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).

Tariff Classification

10. The product under consideration is classified under tariff items 7225 1100, 7226 1100 and 7226 9930 of the Customs Tariff Act, 1975. However, imports of PUC have also been observed in certain other HS Codes viz., 7225 1920, 7225 1990, 7226 1920, 7226 9910, 7226 1990, 7226 99 10, 7226 99 20 and 7226 9990. However, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

11. The Applicant has not proposed any PCN methodology. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

12. Applicant is the producer of CRGO but not Amorphous Metal. Applicant claimed that although Amorphous Metal and CRGO have different physical structures, they serve identical functions, are used by the same consumers for the same end-use, are treated as interchangeable by the market and regulatory bodies and compete directly on price and performance.

13. Applicant claimed that the subject goods and the article manufactured by the Applicant are technically and commercially substitutable. The consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the Applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the Applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from the subject countries.

14. The Applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the Applicant and exported from the subject countries. The article produced by the Applicant and that imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the Applicant are technically and commercially substitutable. The Applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the Applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the Applicant has been prima facie considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. SUBJECT COUNTRIES

15. The subject countries in the present investigation are China PR, Japan, Korea RP and Russia.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

16. The applicant initially proposed Period of Investigation for 9 months i.e. 1st April 2025 to 31st December 2025 (9 Months) and the injury investigation period as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025 and the POI. Subsequently, applicant has requested to revise period of investigation for 12 months i.e. 1st April 2025 to 31st March 2026 as it would enable a more accurate and comprehensive assessment of dumping, injury, and causal link. Hence, the revised period proposed by the applicant has been considered appropriate for the purpose of the investigation and accordingly the Authority has decided to consider the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI") as 1st April 2025 to 31st March 2026 (12 months) and the injury investigation period as 1st April 2022 to 31st March 2023, 1st April 2023 to 31st March 2024, 1st April 2024 to 31st March 2025.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

17. The application for initiation of the present investigation has been filed by JSW JFE Electrical Steel Nashik Private Limited.

18. The Applicant has submitted that NLMK India Coating Private Limited is only other domestic producer of PUC besides the Applicant. Applicant has claimed that NLMK India Coating Private Limited is related to the exporter of the subject goods from Russia and also related to the importer of subject goods in India.

19. It is further submitted that NLMK Group Russia has exported subject goods to India during the injury investigation period in substantial quantities. NLMK India Service Center Pvt. Ltd. is the importer of subject goods from NLMK Group Russia. NLMK India Coating Pvt. Ltd is related to producers and exporters of subject goods in subject country and is also related to importer of subject goods in India. Hence, Applicant has submitted that NLMK India Coating Pvt. Ltd. cannot be considered as an eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

20. The views of another domestic producer namely NLMK has been sought, asking them to submit the information about the imports made by them or related companies from subject country, and whether they are related to producers and exporters of subject goods in subject country and is also related to importer of subject goods in India. NLMK India has submitted that its related entities in Russia, namely, Novolipetsk Steel and Viz Steel Limited Liability Company have made significant exports to India during the injury period including the POI. NLMK India also submitted that it has a related entity in India, NLMK India Service Center Pvt. Ltd. who imported the subject goods from its related entities in Russia, Novolipetsk Steel and Viz Steel Limited Liability Company during the injury period including the POI. The Authority has noted that exports by Novolipetsk Steel and Viz Steel Limited Liability Company /imports by NLMK India Service Center Pvt. Ltd. during the POI are of significant quantities in comparison to total imports from Russia, total Indian production and production by NLMK India.

21. In view of the above, the Authority notes that NLMK India is related to producers/exporters of the subject goods in Russia and is also related to an importer of the subject goods in India. Accordingly, NLMK India does not qualify as an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules.

22. In view of the information furnished by the applicant and the facts noted in the preceding paragraphs, the Authority *prima facie* considers that the Applicant constitutes an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the AD Rules and the application satisfies the requirement of Rule 5(3) of the AD Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value for China PR

23. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

24. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy in a third country. Therefore, the normal value has been constructed based on cost of production of the applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses, with reasonable profit. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

b. Normal Value for Japan, Korea RP and Russia

25. The Applicant has submitted that it was not able to obtain information on comparable prices of the subject goods in Japan, Korea RP and Russia. This information is also not available from any public source. Further, since the subject goods are being imported under various codes, no reliable information was available as regards the representative price of the subject goods when exported from subject countries to third countries. In view of the same, the Applicant has estimated normal value for Japan, Korea RP and Russia based on facts available, having regard to the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits as the basis for normal value. The same has been considered for the purpose of initiation of the investigation.

c. Export Price

26. The Applicant has determined the export price for the subject countries by considering the volume and value of imports as per its market intelligence. However, for the purpose of the determining export price of subject goods from subject countries, DG systems data has been adopted for ascertaining ex-factory export price.

Adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, credit cost, port expenses and handling charges have been made.

d. Dumping Margin

27. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

28. The Applicant has provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as relative terms. There is evidence of price suppression and depression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.

29. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. RETROSPECTIVE IMPOSITION OF DUTIES

30. The applicant has requested for retrospective imposition of the antidumping duty by claiming the following:

    a. There is clear history of dumping of the product from the subject countries.

    b. The importers in India are aware of the fact that exporters practice dumping of subject goods into India. The importers are also aware that such a practice would cause injury to the Indian producers.

    c. The exporters have resorted to massive dumping and dumping margin has remained significant during the period of investigation.

    d. The performance of domestic industry has steeply declined over the period of investigation.

31. Applicant has requested Designated Authority to recommend imposition of anti-dumping duty on a retrospective basis for a period of ninety (90) days prior to the date of imposition of provisional duty.

32. The Authority may seek the views/comments of the interested parties in this regard as per time limit given in the notification.

I. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

33. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the Applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the Applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

J. PROCEDURE

34. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

K. SUBMISSION OF INFORMATION

35. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding SETU Case ID no. No - AD/OI/016/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

36. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

37. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.

38. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

39. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (https://www.dgtr.gov.in/) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. TIME LIMIT

40. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (https://setu.dgtr.gov.in) under their registered name and corresponding case ID – AD/OI/016/2026.

41. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns **within 37 days** from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

42. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.

43. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 41 above of this Initiation Notification.

44. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

45. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified above. Requests submitted after this time will not be considered.

M. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

46. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.

47. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

48. Such submissions must be clearly marked as ‘confidential’ or ‘non-confidential’ at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as ‘non-confidential’ information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

49. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

50. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

51. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.

52. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

53. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

N. INSPECTION OF PUBLIC FILE

54. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. NON-COOPERATION

55. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.06.26 12:55:53 +05'30'